DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur) : The movement of minerals and argicultural goods from western Orissa to eastern Orissa has become very difficult in the absence of direct rail link. The State Government and the Members of Parliament from Orissa have highlighted the prime need of Talcher-Sambalpur rail link time and again which would provide direct connection between Sambalpur and Paradip. Construction of this line would shorten the distance between northern and central India and the eastern coast by nearly 470 kilometres and would effect considerable economy in the cost of transportation. It would reduce the congestion of traffic in the Jharsuguda-Kharagpur section of the South-Eastern Railway.

If this line is constructed, the distance between the aluminimum smelter and alumina plant under construction at Damanjuri and Anugul would be reduced by 75 dms. The rail link would therefore, effect the economy of the project to a considerable extent.

The Talcher-Sambalpur railway line would provide a direct communication between coastal Orissa and western Orissa, a tribal area, rich in mineral and agricultural resources. At present, one has to travel through the State of West Bengal and Bihar in order to reach Sambalpur, the headquarters of western Orissa from the State capital. The proposed railway line is, therefore, vitally important for the growth of the econmy of the State and the esatablishment of much needed emotional integration between the coastal Orissa and western Orissa.

In view of this, I demand that the construction of Talcher-Sambalpur rail link should be taken up during the Sixth Plan period.

(IV) PROBLEM OF DRINKING WATER IN MIRZAPUR AND VARANASI UTTAR PRADESH.

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

वैसे तो आम तौर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पेयजल की कठिनाई प्रतिवर्ष रहा करती है, किन्तु गत वर्ष वर्षा की कमी के कारण वाराणसी तथा मिर्जापुर जिले के कुछ भाग में पानी का स्तर अत्यन्त नीचा होने के कारण पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। वाराणसी के सेवापुरी, भदोही, नवगढ़ आदि विकास खण्डों में तथा मिर्जापुर के अकौड़ी, हलिया, लालगंज तथा दक्षिणी मिर्जापुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कुएं सूख रहे हैं। अनेक गांवों में सूख भी गए हैं। तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर से पीने का पानी ढोया जा रहा है। वहां के निवासियों में पेयजल के संकट के कारण घबराहट उत्पन्न हो रही है। यदि समय रहते उपाय न किया गया तो उक्त क्षेत्रों में पेयजल के अभाव का गम्भीर संकट सम्भावित है। सरकार से अनुरोध है कि पहले तो पेयजल के संकट का मुकाबला करने के लिए उक्त क्षेत्रों में तात्कालिक कदम उठाए जायें। इसके पश्चात् मिर्जापुर तथा वाराणसी जिलों की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए स्थाई योजना क्रियान्वित की जाए।

(V) FINANCIAL ASSISTANCE FOR SLUM CLEARANCE IN PATNA.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं :

श्री रामावतार शास्त्री

बिहार राज्य के विभिन्न भागों में गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं और गन्दगी तथा कूड़े के जमाव के कारण स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में मैं पटना में गन्दी बस्तियों की दशा की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। अत: यह अति आवश्यक है कि गन्दी बस्तियों को शीघ्र समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। केन्द्रीय सरकार को गन्दी बस्तियों को समाप्त करने हेतु वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकार को सहायता करनी चाहिए। ऐसे अनुदान सीधे नगर निगमों तथा नगर-पालिकाओं को देने चाहिए न कि गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के लिए राज्य सरकार के एक मुश्त अनुदान के रूप में।

(VI) ILLEGAL IMPORT OF COCOUNT OIL AT COCHIN PORT.

SHRE E.K. IMBICHIBAVE (calicut An alarming situation has arisen due to the clandastins imports of coconut oil in the name of "Fattyacid" at cochin port. A foregin ship carrying 1450 tons of coconut oil from Penang has started unloading, the coconut oil, markd as raw material for soap manufacturing since last Thursday. This oil is said to be for a soap manufacturing firm in Kerala.

This is yet another example of clandastine import of coconut oil by big traders and big monopolists to cheat thousands of poor farmers of Kerala. Kerala account for 90 per cent of the milling copra produced in the country and this cash crop sustains most of the farmes in the State. That is why we cannot justify the import of the coconut products. The coconut prices are declining. They stood at Rs. 1840 per quintal in November 1980 and went down to Rs. 1250 in July 1981 due to large scale imports. This decline continued in 1982 and due to this the farmers and the State lost Rs. 175 crores each during the last three years. When the price of coconut is falling in the market, prices of all other commodites are rising.

The unscrupulous traders and big businessmen are taking advantage of the loopholes In the Import policy, thus stimulating fall in the prices. The farmers should be guaranteed a stable price for their produce.

The Government must order immediate confiscation of the illegally imported cococut oil. Government also should take strict measures to stop all illegal imports in future.

I also wish the Prime Minister and the Commerce Minister will take note of the seriousness of the issue and take all necessary steps to safeguard the interest of the cultivators.

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय : स्टेटमेंट पढ़िए।

श्री मनीराम बागड़ी : आप खुदाई हुकम अगर चलाना चाहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। नहीं कहने से मैं नहीं मान जाऊंगा। यह बहुत गलत है। आप सुन लो। मैं व्यवस्था का प्रश्न रख रहा हूं।

कायदा आपको पहले बनाना है। आपका कायदा है और उसके मुताबिक कालिंग अटेंशन से पहले इसको आना चाहिए था। आपने पहले नहीं लिया।

सभापति महोदय : आर्डर हो गया था स्पीकर का इसके बारे में।

श्री मनीराम बागड़ी : दूसरी बात यह है कि स्पेशल मेंशन इसलिए रखा जाता है